[Shri S. R. Damani]

suggested four-laning of this road even in the Fourth Plan period at a cost of Rs. 17·5 crores. The portion between Khopoli and Lonawala is particularly hazardous, zig-zag and steep-graded and a large number of accidents and breakdowns are daily occurrences; and hundreds of passengers are killed monthly. The Government of India approved the re-alignment of this portion as far back as March 1973. But implementation was not forthcoming. As a first step, the State Government proposed, to the Government of India to construct a two-lane carriage way that an estimated cost of just Rs. 3 crores. Considering the very heavy traffic on this National Highway, I suggest that (a) the work is of four-laning the road between Panvel and Dahu Road; (b) realignment with a two-lane carriage way between Khopoli and Lonawala and (c) the construction of westerly diversion outside Pune City, can brook no further delay and the Government of India should take immediate action to implement these works.

श्री फिरंगी प्रसाद (बांसगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था क्या है ?

श्री फिरंगी प्रसाद : आप सुन लीजिये। अभी कुछ चन्द मिनट पहले श्री राम अवधेश सिंह ने काका कालेलकर की रिपोर्ट पर बहस के लिए कहा था। मैंने भी उस पर लिख कर दिया है। जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, किसी समय किसी ने कुछ कह दिया और आप इस तरह से उस के लिये खड़े हो जायेंगे, यह ठीक नहीं है।

Now Mr Raj Narain.

(iii) REPORTED SELECTION OF AIRCRAFT FOR INDIAN AIR FORCE.

श्री राज नारायण (रायबरेली): श्रीमन्, सदन को तो ज्ञात ही है कि हमारी वायु सेना को अपने कुछ पुराने विमानों के बदले नये जहाज खरीदने की सख्त जरूरत है। इसके लिये सरकार ने कई कमेटियां भी बनाई थीं। पिछले सैशन में हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री श्याम नन्दन मिश्र ने सवाल उठाया था कि विदेशी पत्रिकाओं में हल्ला है कि विमान को हम चुन चुके हैं, तथा उसके लिए कुछ कमीशन भी बांटे गये हैं। हम यह समझते थे कि सौदा तय करने के पहले इस विषय पर सदन में प्रकाश डाला जायेगा।

यह पुरानी खबर शायद ठीक नहीं थी, पर दस दिन पहले बम्बई के एक साप्ताहिक समाचार पत्र ने बताया कि फ्रांस के एक अच्छे प्रस्ताव को ठुकराया गया है। फ्रांस के प्रधान मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री को पेरिस जाने का निमंत्रण भी दिया था। विश्वस्त सूत्रों से हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि फ्रांस की विमान बनाने वाली कम्पनी, ओ० की० मा०, के अध्यक्ष ने अपने नये प्रस्ताव में कहा है कि उन के मिराज एफ–1 को यदि हम खरीदें, तो साथ ही साथ उन के सबसे नये विमान मिराज 2000 को भी ले सकेंगे और यहां बना सकेंगे। इस प्रस्ताव को अपनी मान्यता देते हुए उनकी सरकार ने भी लिखा था, पर इसका जवाब हम ने देर से और बिना आवश्यकता दिखाते हुए लिखा—इसका जवाब देर से दिया।

साथ ही साथ विदेशी पत्रिकाओं से पता चला कि अमरीका चाह रहा है कि हमें विगेन हवाई जहाज स्वीडेन से न मिले। सुनने में आता है कि सरकारी कमेटी ब्रिटेन के जागुआर विमान खरीदवाना चाहती है, जो कि चार पांच साल के अन्दर यूरोप की वायु सेनाओं की सर्विस से हट जायेगा, यानी वह पुराने टाइप का है।

यह भी एक चिन्ताजनक बात है कि फ्रांस के मिराज तथा स्वीडेन के विगेन के श्रेष्ठ होते हुए भी जागुआर विमान को ही लेने का निश्चय किया जा रहा है। खबर यह भी है कि इस में भारी कमीशन बंटने की संभावना है। ऐसा क्यों हो रहा है, सदन को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में यह बात सारे देश के लिये बहुत ही गंभीर और चिन्ताजनक है। पहली बात तो यह है कि देश के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वायु सेना के बीस साल पुराने विमानों के बदले नये तरह के विमान हम खरीदें, जो कि हमारी जरूरतों को करीब करीब बीस साल तक पूरा करते रहें पर इस के लिए हम ऐसे विमान के लिए नहीं रुक सकते, जो कि अभी डिजाइन ही किया जा रहा है, क्योंकि हमारे आस-पास के देश बहुत ही शक्तिशाली और नये तरह के विमान तथा मिसाइल खरीद रहे हैं, जिस से हम पर आगे वार हो सकता है। इसलिये हमें शीघ्र ही नये तरह के विमान की भी आवश्यकता है। ये ऐसे होने चाहिएं कि उनके नये माडेल को भी हम बाद में आसानी से खरीद सकें तथा भारत में भी बना सकें।

दूसरी बात यह है कि एक तरफ़ से तो सुपर पावर का दबाव पड़ रहा है कि नये तरह के विमान हमें न मिलें और दूसरी ओर सरकार के भीतर का एक "प्रैशर ग्रुप" या "काकस" चाह रहा है कि एक पुराने विमान को हम खरीदें। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण जानना आवश्यक है। सरकार से आग्रह है कि उन कारणों से सदन को अवगत करायें।

श्रीमन्, मुझे कहने का मौका दिया जाये कि यह देश तथा यह सदन इस खेल को चुप-चाप न देखेंगे, जिस में हमारे देश तथा इस की वायुसेना को एक पुराने ढंग का विमान दिया जा रहा है, जिस पर पब्लिक का 1500 करोड़ रुपयों का खर्च है, जब कि और भी अच्छे विमान हमें मिल सकते हैं। सरकार इस बात पर अपनी सफ़ाई दे। हम ऐसा समझौता भी न मानेंगे, जिसमें हमें किसी भी प्रकार

बाध्य किया जाये कि हम अच्छे परीक्षित नये विमानों की जगह पुराने विमान खरीदें, तथा बेचने वालों का वादा मान लें कि आगे चल कर उन के नये विमान को हम खरीदेंगे, जो कि अभी साबित भी न किया गया हो। हमारा नया विमान ऐसा होना चाहिए जो कि बन चुका हो और जिस की खूबियां साबित हो चुकी हों। इस बात पर हम भविष्य में देश की हानि देखने को तैयार नहीं हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैं एक बात की सफाई दे दूं। माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं ने पिछले मार्च में यह कहा था कि कमीशन बांटी गई। मैं ने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि कमीशन बांटने की परिपाटी है और अगर कमीशन बांटी जाती है तो कमीशन राज्य को जाए, किसी व्यक्ति के हाथ न लगे।

(iv) PUBLIC SCHOOL SYSTEM)

SHRI RAJ KRISHNA DAWN (Burdwan) : Sir, under rule 377, I mention the following matter of urgent public importance.

The coaching system in private schools is creating a gap within the society and day by day the gap is widening between the common men and the affluent. As has been seen, every person of privileged class is anxious to get his kid admitted in a private school by paying huge sums which are demanded in the guise of donations. While our leaders make loud promises for Indianisation, they are abolutely keeping their eyes and ears closed as to how the brains of innocent childern are being washed. Instead of making them proud of their heritage, they are made to feel that their culture and way of living in Europe. The typical system adopted by these private schools imparts a perverted culture and makes middle-class sahibs intellectually subservient to half-digested ideas of the middle-class west. Therefore, it is very necessary to go into the details of the functioning of such schools and to determine precisely what kind of a person is created by such institutions. This is a subject which has aroused many suspicions in the minds of the public in general about the way these schools are in operation within the country. They demand higher fees and expect the boys to be better dressed and the medium in all subjects in English. Thereby they create communities of the affluent elites. By destroying their own roots of origin, the boys are alienated from their own people. and remain so far the rest of their live.

It is precisely to avoid the turning out of alienated and rootless young men that 'parents in developed countries have shunned the ideas of public schools system. Yet in India where we need consciously to promote integration, the State continues to tolerate and assist special schools, which turn out potential brown sahebs. It has gone so far as to maintain such schools by direct funding and patronising such a system. It is the time that we should seriously think of discarding such a system which is cutting at the very root of integration and making our children subverters of their own culture and heritage. Although the Centre has not been able to feel the pulse and has realised the extent of damage which such private schools are doing to the nation. Perhaps primarily this is the reason that they have already adopted a unanimous resolution in Delhi Metropolitan Council where they have suggested doing away with the Public School Education System to bring uniformity in the standard of education and have recommended that such schools should be brought at par with those of the Government of Government-aided schools.

It is strongly felt that the Centre should move fast in scrapping out the system of public school education so as to bring an end to corrupt practices by the management of these public institutions throughout India.

(v) REPORTED DEATHS AND HEAVY LOSSES DUE TO RAIN IN HIMACHAL PRADESH.

SHRI DURGA CHAND (Kangra) : I am thankful to the Chair for having permitted me to raise this matter of urgent public importance under rule 377....

This year, Himachal Pradesh has faced heavy and incessant rains causing death of 141 persons. Hundreds of cattle have perished, thousands of houses have collapsed, standing crops have been destroyed and there is heavy erosion of fertile lands, damage to roads, culverts and bridges by landslides, particularly in Kangra, Chamba, Mandi, Bilaspur, Hamirpur and Solan District. The total loss as per reports amounts to several crores of rupees. This is too much for a backward State to bear such a heavy loss on account of natural calamities.

There is an urgent need to provide adequate funds from the Central Exchequer for relief measures in the worst affected regions in the State and to send a Central Study Team to make an on the spot assessment of the havoc wrought by the heavy rains in this State and the damage caused by the earthquake shocks in the Dharmasala area (District Kangra).

———